

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

**ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन एवं सिंचाई व्यवस्थाएँ**

अदिति श्रीवास्तव, शोधार्थी, डिश्वर नाथ खुटे, पीएच-डी, शोध निर्देशक, इतिहास अध्ययनशाला
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE**Authors**

अदिति श्रीवास्तव, शोधार्थी
डिश्वर नाथ खुटे, पीएच-डी, शोध निर्देशक

E-mail : im.aditi.s@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 15/01/2026
Revised on : 19/03/2026
Accepted on : 28/03/2026
Overall Similarity : 00% on 20/03/2026

**Plagiarism Checker X - Report**

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: Mar 20, 2026 (04:44 PM)
Matches: 0 / 2431 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code

**शोध सार**

छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध के कृषि प्रधान देशों में से है। यहां चावल की खेती की प्रधानता के कारण जल की आवश्यकता और बढ़ जाती है। 20 वीं शताब्दी की प्रथम शताब्दी तक सिंचाई के मुख्य साधन तालाब ही थे जो बड़े नहीं थे और जिनका केवल इतना ही महत्व था कि वर्षा के असमान वितरण को तालाब से सिंचाई करके समान किया जाये। मानसून पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जून, जुलाई, अगस्त में जोतने, बोने और ब्यासी (अर्थात् खरीफ की फसल के लिए निदाई) करने और रबी के लिए जमीन तैयार करने की क्रियाएँ होती हैं। इन महीनों की औसत वर्षा (31 इंच से 37 इंच तक) पर्याप्त होती है। छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत ही कम रक्षित भूमि है जहां इन महीनों में वर्षा न होने पर भी खेती का काम यथोचित रूप से चल सके। सिंचाई की वास्तविक उपयोगिता सितम्बर और अक्टूबर के महीने में ही हैं। इन्हीं महीनों में नदियों में भी अनावृष्टि के समय जल कम हो जाता है। कृषि की वास्तविक सफलता ज्यादातर प्रकृति की दया पर निर्भर थी। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम मानसून था। वर्षा समय पर और पर्याप्त होती थी, तब फसल को कोई नुकसान नहीं होता था। जरूरत से ज्यादा वर्षा होने पर फसल नष्ट हो जाती थी। वर्षा न होने पर उपज ही नहीं होती थी, कभी भयंकर तूफान आने पर खड़ी फसल नष्ट हो जाती थी। निश्चित रूप से वर्षा ही किसानों की भाग्यविधाता रही हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में देखें तो स्वतंत्रता के पूर्व 20 वीं शताब्दी में जब छत्तीसगढ़ के इस भू-भाग पर सूखे और अकाल की छाया पड़ी तब यहाँ पर सिंचाई के स्थायी प्रबंध करने के लिए विभिन्न योजनाओं को आकार देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, अकालों पर नियंत्रण रखने एवं कृषकों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। छत्तीसगढ़

की अर्थव्यवस्था में सिंचाई का बड़ा योगदान है। अतीत में देखे तो राज्य के इस भू-भाग पर काफी पहले से ही सिंचाई संसाधनों के विकास की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी।

मुख्य शब्द

ब्रिटिशकाल, छत्तीसगढ़, किसान आंदोलन, सिंचाई व्यवस्थाएँ।

भूमिका

कृषि लघु उद्योग, व्यापार और वाणिज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। आर्थिक विकास देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों के यथासंभव अधिकतम उपयोग पर निर्भर होता है। इस प्रक्रिया में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और कृषि पर आश्रित है। कृषि विकास ना केवल आर्थिक विकास का द्वार है, वरन एक ऐसा उद्देश्य भी है जिसकी पूर्ति सर्वप्रथम की जानी चाहिए उसके पश्चात् दूसरे उद्देश्य तथा औद्योगिक विकास की पूर्ति की जानी चाहिए। आर्थिक विकास का संतोष पूर्ण प्रारंभ कृषि के विकास से ही किया जा सकता है कृषि का विकास किए बिना उद्योगों का विकास संभव नहीं। अनेक प्रकार से कृषि औद्योगिक विकास को सहायता पहुंचाता है। कृषि और औद्योगिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। आर्थिक विकास का इतिहास बताता है, कि विभिन्न देशों के औद्योगिक विकास को कृषि ने पल्लवित कर सरल बनाया है।

छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां धान की कृषि से जुड़ी हैं। यहां के किसान अपने जीवन का अधिकतम समय धान के उत्पादन में ही व्यय करते हैं। रायपुर एवं दुर्ग जिले भी प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र हैं। लोगों के जीवन की तमाम आर्थिक गतिविधियां धान की कृषि के साथ संबंध है। आर्थिक असंतोष के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में समय-समय पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसान आंदोलन एवं विद्रोह व्यापक रूप से होते रहे हैं। सफल किसान आंदोलन के रूप में कंडेल नहर सत्याग्रह को स्मरण किया जाता है। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली के सत्याग्रह में पूर्व का यह आंदोलन प्रचार-प्रसार के अभाव में वह स्थान व महत्व न प्राप्त कर सका जो इसे प्राप्त होना था। कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन जहां एक और किसान आंदोलन था वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन भी था। अंचल में राजनैतिक चेतना लाने में सफल रहा।

ब्रिटिश शासन में कृषि महत्व के प्रतिपादन हेतु धारण प्रणाली की अपनी एक अलग विशेषता रही है। अंग्रेजों ने न्याय के आधार पर निश्चित भूमि धारण प्रणाली की शुरुआत की। ब्रिटिश शासन की व्यवस्था से संबंधित उठाए गए कदमों का पूरा प्रभाव छत्तीसगढ़ के सामाजिक एवं आर्थिक जनजीवन पर पड़ा। इससे समाज की संरचना पर भी प्रभाव पड़ा।

उद्देश्य

- ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख किसान आंदोलन का अध्ययन करना।
- ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों में सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन करना।

किसान आंदोलन

छत्तीसगढ़ के किसानों ने अपने जोर जुल्म से छुटकारा पाने के लिए समय-समय पर आंदोलन प्रारंभ किया गया। ब्रिटिशकाल में छत्तीसगढ़ भू-भाग में हुए किसान आंदोलन एवं उनकी गतिविधियों को क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है¹:

राजनांदगांव बेगार विरोधी आंदोलन (1879)

किसान बेगारी की समस्या से काफी परेशान हो गए थे। सन्-1879-80 में सेवता ठाकुर ने बेगार की समस्या की विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द दी। कंपनी प्रशासन की मदद से उनका विद्रोह कुचल दिया गया।²

कंडेल नहर सत्याग्रह (1920) ई.

छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक धमतरी क्षेत्र में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह का वर्णन न किया जाए। महानदी नहर योजना के अंतर्गत सन् 1912-15 ई. में रुद्री बैराज बनाया गया था जिनका उपयोग नहर नालियों के द्वारा आज पास के गांवों में सिंचाई की जाती थी। सिंचाई विभाग के अधिकारी गांव के किसानों के साथ दस वर्षीय अनुबंध करना चाहते थे किन्तु राशि अत्यधिक होने के कारण गांव के किसान इसके लिये सहमत नहीं हुए। गांव वालों के इंकार करने पर अगस्त 1920 ई. को नहर नाली काटकर पानी खेतों में बहा दिया गया। जिस रात को नहर नाली काटकर खेतों में बहाया गया, उस रात मुसलाधार बारिश हुई। किन्तु कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी बारिश के बाद कोई नहर नाली काटकर पानी ले गया हो।³ सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पानी चोरी का इल्जाम लगाकर 4504 रु. जुर्माने की राशि गाँव गंडेल पर लगा दी। गाँव के देशभक्त मालगुजार बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में किसानों ने जुर्माने की इस राशि का विरोध किया। सत्याग्रह करने का संकल्प लिया। यह इतिहास में कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से विख्यात है।⁴ किसानों की सारी मवेशियों को कुर्क किया गया तथा उसे ही नीलाम कर पैसा वसूलने की कोशिश की। दमनचक्र चलाते हुए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और उनके चचेरे भाई लालजी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बावजूद वहाँ के किसानों के उत्साह में कमी नहीं देखी गयी। नेताओं द्वारा फैसला किया गया कि नेतृत्व गांधी जी को सौंपा जाये। इस संबंध में पत्र लिखकर भेजा गया जिससे गांधी जी तुरन्त तैयार हो गये। रहे। अंत में शासन को झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। पूरी राशि माफ कर दी गई। यह बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कंडेल गाँव के किसानों की अन्याय और अत्याचार के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता थी। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में किसानों का पहला सफलतम सत्याग्रह था। सन् 1920 ई. में महात्मा गांधी के आगमन के पूर्व ही सफलता पूर्वक समाप्त हो गया।⁵

डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन (1937-39)

सन् 1937 में डोंडीलोहारा जमींदारी के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व दुर्ग के युवा अधिवक्ता बन्धु श्री नरसिंह प्रसाद अग्रवाल एवं श्री सरजू प्रसाद अग्रवाल ने किया था। डोंडी लोहारा जमींदारी के जमींदार और उनके दीवान मनाराम पाण्डेय अंग्रेजों के परम भक्त थे। इनकी राजनीति में किसानों में तीव्र असंतोष प्रतीत होता था, क्योंकि इस जमींदारी के किसान जंगल से चरी निस्तारी की सुविधाएँ जमींदारी की स्थापना के पूर्व से ही प्राप्त करते रहे थे, किन्तु एकाएक दीवान ने इन सुविधाओं से किसानों को बेदखल कर दिया, जिसके कारण किसानों ने गांधीवादी सत्याग्रह प्रारंभ कर दी। इस डोंडी सत्याग्रह का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि निस्तारी अधिकार कानून के निर्माण के लिए प्रयास किए गए और कानून बनाए गए। श्री. व्ही. वाई ताम्रकर जी उन दिनों मध्यप्रान्त की विधानसभा में विधायक थे। उन्होंने निस्तारी एवं चरी के लिए बिल लेकर आए।⁶ परिणामतः कमिश्नर एच. व्ही. कॉमथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने समस्त जमींदारियों का दौरा करने के उपरान्त निस्तारी के अधिकार पर 500 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ सुधार किए गए जिनसे किसानों को राहत प्राप्त हुई। पूर्ण सुधार जमींदारी उन्मूलन के बाद हुए।

छुईखदान रियासत में लगान बन्दी आंदोलन (1939)

छुईखदान छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ पर किसानों का भरपूर शोषण व्याप्त था। दीवान, जो कि अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलते थे, उनकी शोषण नीति से किसानों में तीव्र असंतोष था। यही असंतोष 1939 के 'लगान बन्दी' आंदोलन का कारण बना। दिसम्बर 1939 को खैरा नर्मदा में श्री रामनारायण मिश्र के नेतृत्व में किसानों की आमसभा हुई। इसके अंतर्गत शोषण नीति के विरुद्ध लगाबन्दी आंदोलन किए जाने संबंधी निर्णय लिया गया।⁷

कांकेर में किसान आंदोलन (1944-45)

सन् 1944 में दीवान जे. एन. महन्त को हराकर टी. महापात्र को कांकेर रियासत का दीवान बनाया गया। उनसे 1944 में नवीन भू- बंदोबस्त लागू किया गया। नवीन भू-राजस्व व्यवस्था से लोग असंतुष्ट थे। भानुप्रतापपुर

के अंतर्गत गांव सुरंगदाह के गौटिया इन्दर कॅवट ने लोगो को लगान न पटाने के लिए प्रेरित कर आंदोलन की शुरुआत की।⁸

सक्ती रियासत में किसान आंदोलन

सक्ती एक कृषि प्रधान रियासत थी। वहां के उस समय के शासक लीलाधर सिंह की कृषि नीति से गौटियों व किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया। 29 नवम्बर 1947 स्टेट कांग्रेस के नेतृत्व में राजमहल के सामने एक आम सभा हुई। इस सभा में उपस्थित लोगों व प्रतिनिधियों ने रियासत की कृषि नीति की जम कर आलोचना की परन्तु उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई फलस्वरूप कृषक आंदोलन कम नहीं हुए वह राज्य विलय के पश्चात् भी चलता रहा।⁹

ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों में सिंचाई व्यवस्थाएँ

दुर्ग जिला

1. तांदुला तालाब योजना

सन् 1905 में दुर्ग जिले के सबसे बड़े तालाब निर्माण पर सिंचाई हेतु दृष्टिकोण डाला गया। सिंचाई हेतु सन् 1908 में 101.1 लाख प्रस्तावित खर्च की योजना भारत शासन को प्रेषित की गई।¹⁰ भारत शासन के द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सन् 1910 में कार्य प्रारंभ हुआ तथा सन् 1921 में 120.13 लाख के खर्च से यह कार्य पूर्ण हो गया।¹¹ तांदुला तालाब को सबसे बड़ा मिनी जलाशय कहा जाता है, साथ ही विश्व में चौसठवां सबसे बड़ा तालाब होने का सौभाग्य भी प्राप्त है।¹²

रायपुर जिला

महानदी नहर योजना

महानदी में बांध बनाकर वर्षा के पानी को खरीफ की फसल की सिंचाई हेतु परिवर्तित करने की योजना का शुभारंभ सन् 1905 में हुआ। भारत शासन द्वारा इस योजना को सन् 1931 में स्वीकृति प्रदान की गई। सन् 1923 में इस योजना ने पूर्णता को प्राप्त किया।¹³ धमतरी से कुछ दूरी पर दक्षिण-पूर्व में रुद्री नामक स्थान पर 83-87 फुट ऊंचा जलाशय बनाया गया। इस जलाशय को माडमसिल्ली जलाशय के नाम से जाना जाता है। इससे 2,10,000 एकड़ खरीफ फसल सींची जाती है। माडमसिल्ली जलाशय का निर्माण 1915-1923 के मध्य हुआ जबकि रुद्री का मुख्य कार्य 1912-1915 के मध्य पूर्ण हो गया था।¹⁴

बिलासपुर जिला

भारत शासन का यह मत था¹⁵ कि तांदुला तथा महानदी नहर के द्वारा भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई सुविधा हो जायेगी इसलिए इस मत के कारण बिलासपुर जिले में कोई भी वृहद सिंचाई परियोजना जारी करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की किंतु फिर भी सन् 1901 में भारतीय सिंचाई कमीशन ने फसल रक्षार्थ जिस सिंचाई योजना की सिफारिश की थी उसके अनुसार धान की फसल हेतु लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण का कार्य किया गया।¹⁶ सन् 1909 में मध्य प्रदेश शासन की सिंचाई योजनाओं को भारत शासन ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके अनुसार बिलासपुर, दमोह, सागर जिले की 7 लाख की योजनाओं का प्रस्ताव भी सम्मिलित था।¹⁷

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में 20वीं सदी में सिंचाई योजना के जन्म के मूल में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में पड़ने वाले दुर्भिक्षों की विपत्तियां थीं। सन् 1896 और 1899 के अकालों ने काश्तकारों का ध्यान सिंचाई साधनों की ओर आकृष्ट किया। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, अकालों पर नियंत्रण रखने एवं कृषकों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक हैं। सन् 1901-1903 के सिंचाई कमीशन ने अकाल की संभावना वाले क्षेत्रों में रक्षार्थ सिंचाई के साधन जुटाने की सिफारिश की। कमीशन ने छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक क्षेत्रों के लिए लघु सिंचाई योजना की आवश्यकता पर एवं अनावृष्टि से उत्पन्न विपत्ति से रक्षा हेतु इसकी अनिवार्यता पर बल दिया। भारत शासन ने 1909 में छत्तीसगढ़

के लिए प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं पर स्वीकृति इस आधार पर दी कि फसलों की रक्षा हेतु भी सिंचाई योजनाएं आवश्यक हैं। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, अकालों पर नियंत्रण रखने एवं कृषकों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सिंचाई का बड़ा योगदान है।

संदर्भ सूची

1. ठाकुर हेमवती (2012) *छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर का सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन*, वैभव प्रकाशन, रायपुर, प्रथम संस्करण, पृ. 228-229।
2. शुक्ला, शांता (2007) *छत्तीसगढ़ का सामाजिक, आर्थिक इतिहास*, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, पृ. 88-89।
3. पांडे, रीता (2016) *बिलासपुर जिले की भू - राजस्व व्यवस्था (सन् 1861- 1947)*, सर्वप्रिय प्रकाशन कश्मीरी गेट दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 75।
4. शर्मा, तृषा (2004) *छत्तीसगढ़ी इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा*, वैभव प्रकाशन रायपुर (छत्तीसगढ़), प्रथम संस्करण, पृ. 89-90।
5. रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, नागपुर, 1907, पृ. 39।
6. चिशम, जे. डब्ल्यू. (1868) रिपोर्ट ऑन दी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, शासकीय प्रकाशन, नागपुर, पृ. 169।
7. नेल्सन आर. ई. (1909) गजेटियर, दुर्ग जिला, दुर्ग, पृ. 159।
8. नेल्सन आर. ई. (1909) गजेटियर, रायपुर जिला, रायपुर, पृ. 144।
9. शुक्ला, सुरेशचंद्र एवं शुक्ला, अर्चना (2002) *छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास*, मातुश्री पब्लिकेशन, रायपुर (छत्तीसगढ़), प्रथम संस्करण, पृ. 216।
10. ठाकुर, हेमवती (2012) *छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर का सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन*, वैभव प्रकाशन, रायपुर, प्रथम संस्करण, पृ. 124।
11. गुप्त, मदनलाल (1996) *छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन*, भाग-1-2, भारतेन्द्र हिन्दी साहित्य समिति, बिलासपुर, प्रथम संस्करण, पृ. 318।
12. शुक्ला, शांता (2007) *छत्तीसगढ़ का सामाजिक, आर्थिक इतिहास*, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, पृ. 95।
13. मिश्र, रमेशनाथ (2004) *छत्तीसगढ़ का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास*, सेंट्रल बुक हाउस सदर बाजार रायपुर, संस्करण, पृ. 150।
14. शर्मा, अरविन्द (2005) *छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास*, प्रताप टॉकिज चौक, बिलासपुर, द्वितीय संस्करण, पृ. 172।
15. वर्मा, भगवान सिंह (2001) *छत्तीसगढ़ का इतिहास (1818-1854)*, सेंट्रल बुक हाउस, सदर बाजार रायपुर, चतुर्थ संस्करण, पृ. 162।
16. यदु, हेमू (2006) *छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास (प्रारंभिक काल से ब्रिटिश काल तक)*, आर.बी. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 81-83।
17. शुक्ला, शांता (2007) *छत्तीसगढ़ का सामाजिक, आर्थिक इतिहास*, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, पृ. 99-100।
